Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Non implementation of various assurances given by the Government to the farmers regarding MSP, Compensation etc.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। 9 दिसम्बर, 2021 को किसानों को किसान आंदोलन से उठाया गया था। उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे सी टू प्लस 50 पर्सेंट एमएसपी का गारंटी का एक कानून लाया जाएगा।

यह दुख की बात है कि उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे यह कमेटी का गठन हो, जिसमें अभी तक किसानों के साथ तालमेल होकर न कोई एमएसपी की बात हुई, न गारंटी की बात हुई और अब वे एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बार्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

दूसरी बात, इसमें जिन्होंने अपनी जानें गवाईं थीं, जो 850 किसान शहीद हो गए थे, उनके लिए कंपंसैशन उन्होंने मांगा था। जिनके खिलाफ केस किए गए थे, उनके केस वापसी की बात की गई थी। सबसे जरूरी इसमें यह था कि बिजली अमेंडमेंट बिल, इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा, जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो अप्रिहैशंस हैं, उनको अड्रेस किया जाएगा। मैंने बिजनेस में देखा, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसको पिछले सैशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया। अब उसको इस सैशन में लाए। एक टाइम पर किसानों के साथ एक जुबान होती थी, अब तो सरकार की रिटन एश्योरेंस पर भी कोई भरोसा नहीं है।

इसी तरह से बंदी सिखों के संबंध में कहा था कि उनकी रिहाई की जाएगी, लेकिन आज तक बंदी सिखों की रिहाई के लिए कुछ नहीं हुआ। … (व्यवधान)